(घ) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

क्रमांक	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	लाख एकड़ में क्षेत्र का वितरण
1.	आन्ध्र प्रदेश	30.40
2.	असम	3.75
3.	बिहार	9.75
4.	गुजरात	13.81
5.	हरियाणा	0.03
6.	हिमाचल प्रदेश	0.17
7.	कर्नाटक	13.72
8.	केरल	4.57
9.	मध्य प्रदेश	1.71
10.	महाराष्ट्र	10.23
11.	मणिपुर	0.32
12.	पंजाब	1.10
13.	उड़ीसा	6.64
14.	तामिलनाडु	2.07
15.	त्रिपुरा	1.32
16.	उत्तर प्रदेश	22.28
17.	पश्चिमी बंगाल	4.32
18.	गोवा	0.05
19.	मिजोरम	0.74
20.	राजस्थान	0.93
21.	दिल्ली	0.06
	कुल:	127.97

ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक ऋण

523. **श्री नागमणि:** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक कुछ राज्यों में ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए ऋण देने के प्रस्ताव पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या उक्त प्रस्ताव में गुजरात राज्य को शामिल किया गया है;

(ग) क्या विश्व बैंक के किसी दल ने इस संबंध मे कुछ राज्यों का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इस योजना को अन्य राज्यों में भीक्रियान्वित करने का विचार रखती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) से (च) विश्व बैंक की सहायता से विभिन्न राज्यों में कुछेक जल आपूर्ति और पर्यावर्णीय स्वच्छता परियोजनाएं चल रही है। इसके अलावा, विश्व बैंक की सहायता से कर्नाटक में जल आपूर्ति और पर्यावर्णीय स्वच्छता परियोजना तथा महाराष्ट्र में ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावर्णीय स्वच्छता परियोजना चल रही परियोजनाएं हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों में विश्व बैंक की सहायता के लिए ऐसी परियोजनाएं फिल हाल ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय में मूल्यांकन पूर्व/मूल्यांकन की स्थिति में हैं।

"कृभको" में प्रबंध व्यवस्था

524. **श्रीमती मालती शर्मा:**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:
श्री राजनाथ सिंह:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार को "कृभको" में प्रबंध व्यवस्था के बारे में "कृभको" कर्मचारी संघ से एक पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पत्र में क्या-क्या आरोप लगाए गए है;

(ग) उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) उस कार्यवाही का क्या परिणाम निकला है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव): (क) और (ख) मई, 1995 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें अखिल भारत कृभको कर्मचारी संघ के महासचिवों द्वारा निम्नलिखित आरोप लगाए गए हैं:

(i) एकल निविदा आधार पर यू एस ए में डी ए पी संयंत्र लगाने के लिए "यूरोपियन" संविदा प्रदान करना, यद्यपि कृभको ने सिद्धान्त रूप से भारत से बाहर संयंत्र लगाने के लिए भी निर्णय नहीं लिया था।

(ii) नोएडा में प्रबंध निदेशक के नये कार्यालय का एकल निविदा आधार पर 35 लाख रुपए में नवीकरण।

(iii) 1200 रुपए की दैनिक परिलब्धि के साथ कार एवं अन्य खर्चों जिसमें बार-बार विदेशी दौरे भी शामिल हैं पर परामर्शदाता की नियुक्ति।

(iv) 6000 रुपए प्रतिदिन के पारिश्रमिक पर निधि सलाहकार की नियुक्ति।

अखिल भारत कृभको कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने इस बात का समर्थन किया है कि उन्होंने ऐसी कोई शिकायत नहीं की है।

(ग) और (घ) शिकायत की मिथ्या प्रकृति के बावजूद, शिकायत पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच की गई है। किसी भी आरोप की तथ्यों द्वारा पुष्टि नहीं की जा सकती।

Drinking Water Scheme

525. SHRI RAMJI LAL: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether each of the village in the country has so far been provided water under the drinking water scheme together with the State-wise details thereof alongwith those where this facility has not been provided so far;

(b) whether Government will provide more funds under any other scheme to each State including Haryana by the end of this Plan; and

(c) what are the State-wise details of the funds provided by Government for this purpose under the said scheme during the last three years?

THE MINISTRER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) No, Sir, State-wise details of not covered (NC) habitations are given in the Statement I(*see* below).

(b) Central assistance under Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP) will be provided to all the States.

(c) State-wise details of funds released under Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP) during the last three years are given in Statement-II (*see below*).

Statement-I

Sl. No.	State/UT	No. of Not Covered habitations as on 31.1.96
1.	Andhra Pradesh	334
2.	Arunachal Pradesh	222
3.	Assam	12211
4.	Bihar	20029
5.	Goa	55
6.	Gujarat	901
7.	Haryana	0
8.	Himachal Pradesh	5270
9.	J. & K.	918
10.	Karnataka	5710
11.	Kerala	1093
12.	Madhya Pradesh	8440
13.	Maharashtra	0
14.	Manipur	411
15.	Meghalaya	1241
16.	Mizoram	38
17.	Nagaland	358
18.	Orissa	258
19.	Punjab	5439
20.	Rajasthan	12345
21.	Sikkim	20
22.	Tamil Nadu	439
23.	Tripura	763
24.	Uttar Pradesh	13760
25.	West Bengal	0
26.	A&N Islands	11
27.	D&N Haveli	0
28.	Daman & Diu	0
29.	Delhi	1
30.	Lakshadweep	0
31.	Pondichary	0
	TOTAL	90267